











## चमोली त्रासदी: जानकर भी अनजान होने का परिणाम

6

अब इसे त्रासदी कहें या हादसा या फिर आप बुलाई आपदा जो भी, लेकिन सच यही है कि 2013 में भी इसी उत्तराखण्ड की केंद्रानाथ त्रासदी की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें और रिपोर्ट्स चल चित्र जैसे घूमने लग जाती हैं। 16 जून 2013 की रात को उत्तराखण्ड ही क्या पूरा देश कभी भूल नहीं सकता। कुदरत के कहर की वैसी ही भयावह तस्वीरें फिर सामने हैं। फर्क बस इतना कि तबाही तो जमकर हुई लेकिन संतोष इसी बात का है कि तब के मुकाबले अब बहुत कम लोग काल कलवित हुए। हालांकि सटीक आंकड़ा आने में अभी समय लगेगा। लेकिन नुकसान की तस्वीरें ने तब केंद्रानाथ का जो डरावना सच दिखाया था लगभग वैसा ही अब है।

तो क्या चमोली में जो कुछ हुआ वह जलवायान साधन संपन्न होती दुनिया के लिए अभी भी चेतना जाने की दस्तक ? कुछ भी करें लेकिन सच यह है कि अब से 8 महीन पहले ही वैज्ञानिकों ने आगाही कर दिया था और इसको लेकर जर्नल साइंसेस एडवांस 2019 में एक रिसर्च भी छपी थी जिसमें बड़े लिके में ग्लोबल वार्मिंग के तेजी से पिघलने तथा इसको लेकर 40 वर्षों के अध्ययन जिसमें सैटेलाइट सर्वेक्षण और तस्वीरों के विश्लेषण करनी जाई शामिल है में अदिशा जाताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के ग्लोबल रहे हैं। इसे अनुदेखा किया गया था। आँकड़े और अध्यन बताते हैं कि पिछले 25 वर्षों यानी 1975 से 2000 तक के मुकाबले 2000 से 2016 तक वहाँ का तापमान लगभग एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। जहाँ वर्ष 2000 तक यानी बीते 25 वर्षों में केवल ग्लोबल वार्मिंग से चैर्थाई मीटर तक बर्फ पिघलती थी वहीं 2000 के बाद पिघलन दर दो गुनी से भी ज्यादा हो गई। स्वाभाविक है कि सारा कुछ ग्लोबल

वामिंग का खेल है। लेकिन हैरानी है कि गुपचुप ग्लेशियर पानी में तब्दील होते रहे और हुक्मरान व अफसरान सब बेखबर रहे! उन्हें ग्लेशियरों का नतीज रिवावार को अपने रैद्र रूप में सात साल, सात महीने, 25 दिन बाद फिर सामने आया। इस बार भी देवधूमि उत्तराखण्ड ही फिर निशाना बनी।

अब इसे त्रासदी कहें या हादसा या फिर

वाले हिमालय को लेकर जितनी जानकारी है उसमें  
यह संक्षेप खत्म होने से रहा क्योंकि न तो ज्यादा  
डेटा है और न ही रिसर्च आकृटिक और अंटार्टिक  
के बाद दुनिया का तीसरा ध्रुव इसी हिमालय क्षेत्र के  
हिन्दू कुश भी कहते हैं। जो हिमालय क्षेत्र  
अफगानिस्तान, बांगलादेश, भूटान, चीन, भारत  
किर्गिजस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल  
पाकिस्तान तजिकिस्तान और उज्जेकिस्तान तक

निजी स्वामित्व वाली 130 मेगावॉट की ऋत्यंगंगा पनविजली प्रोजेक्ट जहाँ पूरी तरह तबाह हो गया है वहीं निमार्णाधीन 520 मेगावॉट की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को भी भारी नुकसान हुआ है। अमूमन जब ग्लेशियर के पिघलने से बने हिमनद एकाएक झील में तब्दील हो जाते हैं तो काफी पानी जमा हो जाता है और जमे हड्डी बर्फ को थामें ग्लेशियर या तो बजन से या

1

# संपादकीय वार्ता की पहल



कृषि कानूनों के खिलाफ 75 दिन से आंदोलन कर रहे किसान नेता एक बार फिर सरकार से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने यह फेसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया। मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में किसान नेताओं से अपील की थी कि विरोध खत्म कर बातचीत के लिए आगे आएं। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि वे अगले दो दिनों की बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार उन्हें मीटिंग का दिन और समय बता दे। इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा, मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में नई जमात पैदा हुई है। एक नई बिरादरी सामने आई है- आंदोलनजीवी। आप देखेंगे कि आंदोलन चाहे वकीलों का हो, स्टूडेंट्स का हो, मजदूरों का हो, हर आंदोलन में ये जमात नजर आएंगी। ये आंदोलन के बिना जी नहीं सकते। हमें इन्हें पहचानना होगा। इस बयान पर किसान नेताओं ने आपत्ति जताई है। किसान और सरकार के बीच अब तक 12 दोर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। वहीं सरकार कह रही है कि वह कानूनों में बदलाव करने को तैयार है और किसान चाहें तो तीनों कानून डेढ़ साल तक होल्ड भी किए जा सकते हैं। दोनों के बीच अखिरी मीटिंग 22 जनवरी को हुई थी। अब तक दोनों ही पक्ष जिस तरह से अपनी-अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उससे कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिलता। हठधर्मिता का ऐसा रुख किसी भी तरह से परिवर्ता का परिचायक नहीं कहा जा सकता। सरकार बार-बार स्पष्ट शब्दों में इस बात को दोहरा रही है कि कुछ भी हो, कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। दूसरी ओर किसान संगठनों ने भी ठाठ लिया है कि जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। रही बात एमएसपी की तो प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के मंत्री अगर बार-बार कह रहे हैं कि वह खत्म नहीं होगी तो किसान नेताओं को भरोसा करना होगा। माना कि किसान मले अपने जायज मांगों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, वह भी नंगीर चिंता की बात है। आए दिन पक्ष-विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किसान हितों के साथ खिलावड़ करने, किसानों को बहकाने और आंदोलन को हवा देने के जो आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे यही संदेश जा रहा है कि यह किसानों का आंदोलन कम, राजनीतिक खंचितान ज्यादा है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के बाद किसान संगठन ही आपस में बंट गए हैं। ज्यादातर किसान संगठन नए कृषि कानूनों को जहां किसान हितों के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं कुछ किसान संगठन इसके समर्थन में उतर आए हैं। सवाल है कि इन कानूनों को लेकर किसानों के मन में जो भय और आशंकाएं हैं, उन्हें सरकार क्यों नहीं दूर कर पा रही है। अगर सरकार एमएसपी और मंडियों को खत्म नहीं करने का भरोसा लिया कर देने को तैयार है तो क्यों नहीं वह किसानों को यह समझा पा रही है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने में अड़चनें तय हैं। किसान आंदोलन लंबा खिंचने से आमजन को भारी समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों की सीमा पर आवाजाही एक तरह से ठप है। राज्यों के बीच होने वाली सामान आपूर्ति पर असर पड़ा है, कच्चे माल की कमी से दिल्ली की औद्योगिक गतिविधियां ठप पड़ चुकी हैं। किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर आतंकार्दी अनुरूप कर रखी है।

# भारत देश और उसकी गौरव गाथा



‘जब जीरो दिया मेरे भारत ने  
भारत ने मेरे भारत ने  
दुनिया को तब गिनती आयी’

ल एक गाना नहीं बल्कि भारत की वो गैरव  
नसपर हम सभी भारतीयों को गर्व करना  
भारत जो ईरान की छोर से लेकर इंडोनेशिया  
फैला हुआ था ज्ञान और वैधव में अद्वितीय,  
बरसे पुरानी सभ्यता वाला देश वो देश जिसके  
की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान  
का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म  
ना जाता हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता जो विश्व  
वहला ज्ञात स्थायी और मुख्य रूप से नगरीय  
उदाहरण है। इसका विकास 3500 ई०प० से  
पूर्व तक हुआ सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण  
शास्त्रीय द्विसे में एकी एकी निसे आज  
सभ

A painting depicting a scene from ancient Mesopotamia, likely Ur. The scene shows a city street with several brick buildings. In the foreground, a man sits on the ground near a doorway. Another man stands nearby. In the background, more buildings and figures are visible, including a person on a roof. The style is characteristic of ancient Mesopotamian art.

जेनमें तैयार पहनी शारीरिकों ने अकूत और हासन वकता बाह ने आ था। भारत में आंकीट की युद्ध में संस्करण इसके उत्पादन को एथे। भग 1 नीथि। धनी र लूट इसकी रुपये बहुत पहले 1000 1000- . एक भारत देश के सोने है कि म है। जेनमें तैयार पहनी शारीरिकों ने अकूत और हासन वकता बाह ने आ था। भारत में आंकीट की युद्ध में संस्करण इसके उत्पादन को एथे। भग 1 नीथि। धनी कि केरल सरकार की वार्षिक आय 1.03 लाख करोड़ है जो कि केरल के पद्मनाभस्वामी मर्दिंग के किसी गर्भ गृह के एक कोने में ही मिल जायेगा। इसा की पहली सदी से भारत विश्व का सबसे बड़ा विनिर्णय केंद्र था। जो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के द्वारा विश्व में किया जाता था विश्व की जो भी आवश्यकता थी वह भारत के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। भारत वस्त्र, मसाले, मोती, चीनी और लोहे के हथियारों का एक प्रमुख निर्यातक था। इसके अलावा कपास, चावल, गेहूं, चीनी जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे, इसके अलावा आटू, नील, तिल का तेल, हरी, नीलमणि आदि के साथ-साथ पशु उत्पाद, रेशम, चम्पफ्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चार्दी के बने पदार्थ आदि का भी निर्यात करता था। 600 इ.स के आस-पास महाजनपदों ने चांदी के सिक्कों के साथ सिक्का प्रणाली शुरू की थी। ग्रीक के साथ-साथ पैसे पर आधारित व्यापार को अपनाने वाले पहले देशों में भारत का स्थान अग्रणी था। लगभग 350 ईसा पूर्व, चानक्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य के लिए आर्थिक संरचना की नींव डाली थी। मुगलों के शासन शुरू करने से पहले, भारत 1 A.D और 1000 A.D के बीच दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी जब मुगलोंने 1526-1793 के बीच भारत पर शासन किया, इस समय भारत की आय (17.5 मिलियन पाउंड), ग्रेट ब्रिटेन की आयसे अधिक थी। वर्ष 1600 A.D में भारत की प्रति व्यक्ति GDP 1305 डॉलर थी जबकि इसी समय ब्रिटन की प्रति व्यक्ति GDP 1137 डॉलर, अमेरिका की प्रति व्यक्ति GDP 897 डॉलर और चीन की प्रति व्यक्ति GDP 940 डॉलर थी। इतिहास बताता है कि मीर जाफर ने 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3.9 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। 1500 अ.स के आस-पास दुनिया की आय में भारत की हिस्सेदारी 24.5% थी जो कि पूरे यूरोप की आय के बराबर थी। लेकिन जब अंगैज भारत को छोड़कर गए तो भारत का विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान मात्र 2 से 3% रह गया था, लेकिन आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

# जंग जारी कृषि कानूनः खुन से खेती या खेती का खुन....

आमप्रकाश मेहता

करीब पचहत्तर दिनों से कथित कृषि काले कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन को लेकर सरकार की तल्खी बढ़ती जा रही है, सरकारी प्रशासन जहां दिल्ली के प्रवेश द्वारों पर नुकीलें सरिये गाड़ रहा है, वहाँ केन्द्रीय कृषि मंत्री जी का संसद में क्षेत्र-नामांगणना करने वाले और उनकी विधायियों को प्रत्यक्ष कदम पर पुलस व सुरक्षाकामया क्षेत्र बनानियां स्थापित कर रही है, सरकार की इसी परेशानी को धांप कर किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को घोषित तीन घण्टे के राजमार्गीय चक्कर जाम से दिल्ली, उत्तरप्रदेश व उत्तराखण्ड को मुक्त कर दिया।

प्रशासन जहां दिल्ली के प्रवेश द्वारों पर नुकीलें सरिये गाड़ रहा है, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री जी का संसद में क्रोध चरम पर पहुंच रहा है और उनकी टिप्पणियों को संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ रहा है, वहीं यदि आंदोलनरत किसानों की कार्यशैली ठीक सरकारी जाम से दिल्ली, उत्तरप्रदेश व उत्तराखण्ड को मुक्त कर दिया।

अब तक किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस सहित करीब दो दर्जन छोटे बड़े प्रतिपक्षी दलों का समर्थन था, यद्यपि इन्हें आंदोलनरत किसानों ने उनके

A color photograph of an elderly Indian man with a white beard and mustache, wearing a traditional orange turban and a light-colored kurta. He is smiling and holding a bunch of green onions in his hands. The background is a lush green field under a clear blue sky.

साथ मंच साजा भी नहीं करने दिया, संसद में भ्रम प्रतिपक्षी दल किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, किंतु अब एक आश्वर्यजनक तथ्य यह सामने आ रहा है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा को भर्त

इस आंदोलन की राजनीतिक दृष्टिकोण से चिंता सताने लगी है, क्योंकि पंजाम-हरियाणा का जाट समुदाय इस आंदोलन से जुड़ा है जो पंजाब-हरियाणा में भाजपा का मुख्य आधार बोट है, शायद इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस किसान आंदोलन के सुखद समापन के बारे में गंभीर चिंतन शुरू कर दिया है, किंतु देश महसूस कर रहा है कि इस विवाद को लेकर पिछले ढाई महीने में कृषि मंत्री जी इतने अधिक परेशान हो गए है कि उनकी तल्खी अब खुलकर सामने आने लगी है शायद कृषि मंत्री के इसी रूच के कारण किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता राकेश टिकैत ने अब सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी से ही विवाद के बारे में चर्चा करने की ठांठली है, उन्होंने यह कहते हुए कृषि मंत्री को और चिंडा दिया कि कृषि मंत्री वही बोलते हैं जो

उनके अधिकारी उन्हें लिखकर दे देते हैं, इसलिए  
अधिकारियों का कथन मंत्री के मूँह से सुनने की  
अपेक्षा अब प्रधानमंत्री से ही इस बोर्ड में चर्चा होगी।

जो भी हो, किंतु अब यह तय है कि किसान  
संगठन और सरकार दोनों ही चाहते हैं कि इस  
आंदोलन का सुखद समापन हो, शायद इसीलिए  
किसान नेता राकेश टिकैट ने सरकार को विवादित  
कानूनों को वापस लेने की आठ महीनों की मोहल्लत  
दे दी है और कहा है कि सरकार दो अक्टूबर छांगांधी  
जयंतीहां तक तीनों विवादित कृषि कानून वापस ले  
ले, वर्ना उसके बाद चालीस लाख ट्रेक्टरों की रैली  
पूरे देश में भ्रमण कर आंदोलन को तीव्र करने की  
अलख जगाएगी और तब तक किसानों का शांतिपूर्ण  
आंदोलन भी जारी रहेगा।

अब देश पर राज कर रही भाजपा की सबसे बड़ी

और अहम् चिंता यह है कि वह किसानों के आंदोलन से निपटे, अपने बोट समेटे या पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में निकट भविष्य में ही होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति को अंजाम दे ?

इस प्रकार किसान आंदोलन अब सरकार व सत्तारूढ़ दल दोनों के ही लिए अच्छा खासा लूंसिरदर्दह्य बन चुका है, क्योंकि अब इस आंदोलन को विदेशी समर्थन भी मिलने लगा है, अमेरिका के बाद रूस और अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किसानों के समर्थन में भारत सरकार को सीख दी है, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि कृषि मंत्री जी को खेती और खून का तालमेल करने के बजाए तल्खी छोड़ शांति से आंदोलन के सुखद समापन के बारे में गंभीर चिंतन करना चाहिये ।

भादि से संपादक का सहमत











